

‘अगर केरल में जीतना है तो वेणुगोपाल को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर वहाँ भेजो’

कांग्रेस में यह आवाज जोरों से उठ रही है, पर, सवाल यह है कि यह मांग वेणुगोपाल को गौरवान्वित कर रही है या उनकी खिल्ली उड़ा रही है?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक जंग का माहौल है, अगर पार्टी को केरल में जीतना है तो के.सी. वेणुगोपाल को केरल भेजो बतौर पीसीसी अध्यक्ष, अन्यथा वाम मोर्चा राज्य में रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आ सकता है!!

क्या यह चुटकी ली जा रही है, क्योंकि पार्टी के कई गुट चाहते हैं कि वेणुगोपाल, एआईसीसी से और कांग्रेस की सत्ता से बाहर हो जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद को पार्टी का निर्विवाद राजा बना लिया है, उन्हें राहुल गांधी के वीडो के साथ और उनका पूरा विश्वास और समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी ने अपनी निर्णय लेने की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा के.सी. वेणुगोपाल को सौंप दिया है और इससे कांग्रेस के कई नेताओं को भारी नाराजगी है, जो महसूस करते हैं कि वेणुगोपाल अपनी मर्जी से काम करते हैं और पार्टी के हित को ध्यान में नहीं रखते।

- अधिकतर नेतागण वेणुगोपाल को केरल इसलिए भेजना चाहते हैं, जिससे ए.आई.सी.सी. में घुटन कम हो।
- वेणुगोपाल पर राहुल गांधी को इतना “भरोसा” है, कि जब तक वेणुगोपाल की मोहर नहीं लगती ए.आई.सी.सी. में कोई काम नहीं होता।
- अच्छे-अच्छे नेता भी इस कथन की सत्यता से पूरी तरह वाकिफ हो गए हैं तथा उन्हें वेणुगोपाल के सम्मुख नतमस्तक होना ही पड़ता है। यहाँ तक कि राहुल के नज़दीकी व विश्वासपात्र अजय माकन भी अब वेणुगोपाल के साथ मिलकर काम करने में ही अपनी भलाई देख रहे हैं।
- वेणुगोपाल ने हर राज्य में एक अपना मनपसंद प्रभारी नियुक्त कर रखा है और ये प्रभारी वेणुगोपाल के मन के अनुरूप राज्य में कांग्रेस को चलाते हैं।

कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने के.सी. वेणुगोपाल के आगे समर्पण कर दिया है, और वे उनके आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते

हैं कि राहुल गांधी तक पहुँचने का रास्ता के.सी. वेणुगोपाल के माध्यम से ही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के एक वफादार और करीबी साथी अजय

माकन, जो एआईसीसी के कोषाध्यक्ष हैं, को भी किसी निर्णय पर अंतिम मुहर लगाने से पहले वेणुगोपाल से मिलना पड़ता है।

क्योंकि राहुल ने माकन को कह दिया है कि उन्हें वेणुगोपाल से बात करनी चाहिए।

के.सी. वेणुगोपाल और अजय माकन ने इंदिरा भवन से काम करने का निर्णय लिया है, बजाय 24 अकबर रोड के।

क्यों, जबकि कोई कार्यक्रम इंदिरा भवन तक पहुँच ही सकता और किसी नेता से मिल भी नहीं सकता? इसका उत्तर एक पुराने कांग्रेस विश्लेषक से मिला, जो कहते हैं कि माकन व वेणुगोपाल चाहते हैं कि सार्वजनिक संपर्क, जितना संभव हो सके, कम रखा जाए।

और बाकी महासचिव और राज्य प्रभारी का क्या, वे पार्टी कार्यालय क्यों नहीं आते और वहाँ से काम क्यों नहीं करते?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘महबूबा ने भी एक महिला का बुर्का उतरवाया था’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा, “लोग शायद इस बात को भूल गये हों कि महबूबा मुफ्ती ने एक वैध मतदाता का बुर्का एक मतदान केन्द्र के अंदर हटवाया था। यह उसी मानसिकता की निरंतरता है।” उमर, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिजाब विवाद पर आलोचना करने वाले पहले नेताओं में से थे, ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी महबूबा पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एक साम्प्रदायिक पार्टी के सहयोगी के रूप

- जम्मू कश्मीर के मु.मंत्री उमर अब्दुल्लाह ने याद दिलाया कि मतदान केन्द्र में महबूबा मुफ्ती ने वोट डालने आई एक महिला का बुर्का उतरवाया था।

में एक महिला डॉक्टर का बुर्का हटाकर, “अपना असली रंग दिखा रहे हैं।” अब्दुल्ला ने याद दिलाया कि यह ट्रेंड महबूबा ने ही शुरू किया था। ज्ञातव्य है कि अप्रैल 2004 के चुनावों के दौरान, मुफ्ती ने एक महिला का बुर्का उड़ाया था। जब इसके लिए उनकी आलोचना की गई, तो उन्होंने कहा था कि वह मतदाता की पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि बुर्के का इस्तेमाल अक्सर झूठे वोट डालने के लिए किया जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नारी सशस्त्रीकरण का नारा अति प्रचलित है आजकल राजनीति में’

प्रशांत किशोर ने डेढ़ घंटे की मुलाकात में प्रियंका गांधी को यह “नेक” सलाह दी कि उन्हें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कांग्रेस की राजनीति में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से हाल ही में हुई मुलाकात दरअसल सिर्फ इतना ही दर्शाती है कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक कांग्रेस के साथ संभावना एवं अवसर की एक खिड़की खुली रखना चाहते हैं।

नई दिल्ली में दोनों नेताओं की डेढ़ घंटे की इस मीटिंग के बाद राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई कि किशोर ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद के बदले जन सुराज पार्टी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव रखा है। लेकिन जेएसपी के सूत्रों ने ऐसी संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि पीके खुद को इस तरह कम करके नहीं आँकते।

हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों में कांग्रेस और जन सुराज पार्टी, दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस ने जिन 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से वह सिर्फ छह पर जीत हासिल कर सकी, जबकि जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी जमानत जबा हो गई। संभवतः दो पराजित दलों

- प्रशांत किशोर का मानना है कि राजनीति में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं. अतः कुछ समय बाद, कालांतर में कांग्रेस की स्थिति में सुधार अवश्य होगा और वे कांग्रेस के लिए अवैतनिक (फ्री) सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं।

- जैसा कि विदित ही है, बिहार चुनाव में दोनों पार्टियों, कांग्रेस व प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, की बहुत खराब हालत हुई थी। कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तथा केवल छः सीटों पर ही जीत पाई तथा जन सुराज पार्टी 236 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तथा सभी सीटों पर जमानत नहीं बचा पाई थी।

- प्रशांत किशोर सदा राहुल से ज्यादा प्रियंका के नज़दीक थे तथा 2017 के यू.पी. के चुनाव में कांग्रेस की रणनीति तैयार करते समय, उन्होंने प्रियंका गांधी को मु.मंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने की राय दी थी।

- प्रियंका भी काफी इच्छुक थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस जाँइन कर लें।

- अब प्रियंका गांधी से मुलाकात करके प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए एक खिड़की खोल ली है।

का विलय बिहार में या कहीं भी कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘बोतलबंद पानी की अशुद्धता की याचिका शहर केन्द्रित सोच का प्रतीक’

सी जे आई ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए “लगज़री” मुकदमा और अमीरों की चॉचलेबाजी करार दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका को नकारते हुए कहा कि भारत की बड़ी आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बुनियादी पेयजल तक से वंचित है। कोर्ट ने इस याचिका को “लगज़री मुकदमा” करार देते हुए, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार तक करने से इंकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच, सारंग वामन यादवड़कर द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि देश में बिकने वाला पैकेज्ड पानी विकसित

- याचिकाकर्ता की वकील अनिता शेनॉय ने कहा कि यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और उपभोक्ता को स्वच्छ व शुद्ध बोतलबंद पानी मिलना चाहिए और इसमें डब्ल्यू एच ओ के मानकों का पालन होना चाहिए
- चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने याचिका पर कड़ी टिप्पणी की और कहा, जब गांधी जी भारत लौटे थे, तो गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों में गए थे, याचिकाकर्ता से कहिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाए और देखे कि लोग पीने का पानी पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, तब उसे समझ आएगा, असली भारत की तकलीफ क्या है।

देशों के मानकों, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक शामिल है, के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता ने पैकेज्ड पानी के गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने और फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड

अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ एस एस ए आई) के तहत बोतलबंद पानी के नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आदेश देने की मांग की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट में लोक अदालत आज

जयपुर, 18 दिसंबर। राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब लोक अदालत की शुरुआत दोपहर 3.30 बजे से होगी। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जयपुर पीठ में लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। इसी तरह

- राजीनामा करने के लिए जयपुर व जोधपुर में तीन-तीन बेंच बनाई गई हैं।

जोधपुर में जस्टिस पुणेन्द्र सिंह भाटी इसकी शुरुआत करेंगे।

जयपुर पीठ में मुकदमों के आपसी राजीनामे के जरिये निपटारे के लिए तीन बेंच बनाई गई हैं, जिनकी अध्यक्षता मौजूदा न्यायाधीश प्रवीर भटनागर, जस्टिस संदीप तनेजा और जस्टिस बिपिन गुप्ता करेंगे। वहीं, इनमें सदस्यों के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एसके गुप्ता, महेन्द्र शाह और अजय कुमार बाजपेयी को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीति आयोग के पूर्व कर्ताधर्ता अमिताभ कांत सरकार से इतने रुष्ट क्यों हैं?

अमिताभ कांत की पीड़ा यह है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के नाम पर नये-नये मापदंड लाए जा रहे हैं, एम.एस.एम.ई. सैंक्टर पर, जिससे भारत में निर्मित माल, विश्व की सप्लाई शृखंला का हिस्सा नहीं बन पा रहा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भारत के तेजी से बढ़ते क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) सिस्टम की अब तक की सबसे तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि जिसे आधिकारिक तौर पर स्टैंडर्ड और सुरक्षा अभ्यास के रूप में पेश किया जा रहा है, वह असल में संरक्षणवाद का सीधा हथियार बन गया है, जो प्रतिस्पर्धा, रोजगार और एमएसएमई को नुकसान पहुँचा रहा है।

‘पॉडकास्ट “यो”’ में मोनिका हलान से बातचीत करते हुए कांत ने कहा कि क्यूसीओ का व्यापक और बेतहाशा विस्तार, जो अब 760 से अधिक उत्पादों और क्षेत्रों को कवर करता है, “संरक्षणवाद का सबसे खराब रूप” है।

- क्वालिटी कंट्रोल के यह मापदंड 760 प्रोडक्ट्स व सैंक्टर पर लगाये गए हैं तथा ज्यादा वेदना का विषय यह है कि ये मापदंड “इनपुट” (निर्माण) में काम आने वाले सामान पर लागू किए गये हैं। मापदंडों की पालना से भारतीय सामान महंगा होता जा रहा है तथा अन्य प्रतिस्पर्धी देश अपना सामान भारत की तुलना में सस्ता बेच रहे हैं और भारत अपना निर्यात बढ़ाने का सुअवसर खोता जा रहा है।

खासतौर पर इसलिए, क्योंकि इनमें से कई आदेश अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर नहीं, बल्कि कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों और पुर्जों पर लगाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यहीं पर भारत खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

कांत के मुताबिक, इनपुट्स (उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल) पर बाधाएँ बढ़ाकर क्यूसीओ गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं की तरह

काम करते हैं। इससे आयात सीमित होता है और घरेलू निर्माताओं के लिए लागत बढ़ जाती है। कांत ने कहा, इसका सबसे ज्यादा बोझ एमएसएमई पर पड़ता है, जिनके पास न तो इतनी बड़ी क्षमता होती है और न ही सौदेबाजी की ताकत

कि वे ऊँची इनपुट कीमतों या जटिल अनुपालन नियमों को आसानी से झेल सकें। नतीजा यह होता है कि भारतीय कंपनियाँ वैश्विक वैल्यू चेन में कम अनुसार, कच्चे माल और पुर्जों को बेवजह महंगा बनाकर भारत की विकास कहानी को नुकसान पहुँचा रहा है।

प्रतिस्पर्धी बन जाती है, जिससे सरकार द्वारा समर्थित मैनुफैक्चरिंग और निर्यात महत्वाकांक्षाएँ ही कमजोर होती हैं।

कांत ने कहा कि समस्या अब सीमित या लक्षित हस्तक्षेप तक नहीं रही है, बल्कि यह बेकाबू विस्तार का रूप ले चुकी है। बोते एक साल में ही सैकड़ों नए क्यूसीओ जारी किए गए, वह भी अक्सर बिना पर्याप्त परामर्श के। इससे विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट लागत बढ़ी है, मुनाफे के मार्जिन सिमटे हैं और कंपनियाँ वैश्विक उत्पादन नेटवर्क से जुड़ने से हतोत्साहित हुई हैं। कुछ खास उत्पादों के लिए सीमित क्यूसीओ को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन मौजूदा “बेलगाम” फैलाव, उनके अनुसार, कच्चे माल और पुर्जों को बेवजह महंगा बनाकर भारत की विकास कहानी को नुकसान पहुँचा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरिस्का के बफर ज़ोन में आग लगी

अलवर, 18 दिसम्बर। अलवर शहर से लगते सरिस्का टाइगर रिज़र्व के बफर ज़ोन के जंगल में देर रात करीब 8 बजे अलाव की चिंगारी से आग लग गई, जिसके कारण वनकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। दरअसल, बफर ज़ोन के जंगल में 10 से अधिक टाइगर और 30 से अधिक लेपर्ड हैं। वनकर्मियों और दमकलकर्मियों ने मिलकर रात करीब सवा बजे आग बुझाई। आमजन ने घरों की छत से वीडियो भी बनाए।

सरिस्का के एक कर्मचारी ने बताया, चौबुर्जा के आसपास के जंगल में ऊंची पहाड़ी पर आग की लपटें जब

- सौ हैक्टर में लगी आग पाँच घंटे में काबू में आई।

शहर में घरों की छतों से साफ नजर आने लगीं, उसके बाद आग लगने का पता चला। फिर तुरंत वनकर्म सागर की तरफ से पहाड़ी पर चढ़े। करीब 20 से 30 कर्मचारियों ने मिलकर आग को बुझाया।

दमकल भी मौके पर पहुंची। लेकिन उसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके कारण दमकल का कोई उपयोग नहीं हो सका। मोहल्ले के कुछ लोग भी वनकर्मियों के साथ आग बुझाने के लिए पहाड़ पर चढ़े।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

सत्याग्रह बल प्रयोग के विपरीत होता है। हिंसा के संपूर्ण त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है। –महात्मा गांधी

महाअभियोग के संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग न्यायाधीश स्वामीनाथन के विरूद्ध न केवल अलोकतांत्रिक है, अपितु न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कटु प्रहार है

देश के 56 सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें संसद के उन सदस्यों को विद्बो करने का आग्रह किया है, जिसके द्वारा उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के विरूद्ध महाअभियोग की कार्यवाही करने की मांग की है। संसद के अध्यक्ष को प्रेषित किया है उसकी प्रक्रिया की कटु आलोचना की है। उनका कथन है कि यह कार्य संविधान के प्रावधानों की गरिमा उद्देशिका में वर्णित मूल भवना तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कटु प्रहार है।

अपने पत्र में 50 पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार दिये हैं कि कुछ सांसदों और एडवोकेट्स न्यायालय (न्यायाधीशों) को दबाव में लाना चाहते हैं, वह भी केवल इसलिये कि वे लोग जस्टिस महोदय की राजनीतिक अथवा Ideological विचार धारा से सहमत नहीं हैं। यह सोच न्यायाधीश स्वतंत्रता के विरूद्ध है व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत है।

यह घटना क्रम उस समय हुआ, जब जस्टिस स्वामीनाथन ने एक पिटीशनर को पिटीशन पर जो अपने को Right Wing Activist मानता है, जस्टिस स्वामीनाथन ने, सुनवाई के बाद यह निर्देशन राज्य सरकार को दिया कि पवित्र दीपक पहाड़ी शिखर पर प्रज्वलित किया जा सके इसकी व्यवस्था हो ताकि कोई व्यवधान न हो। राज्य के अधिकारियों का कथन था कि दीप मंडप के सामने दीपक जलाने की प्रथा बहुत पुरानी है। मस्जिद और दीप दोनों पहाड़ी की चोटी पर हैं बीच में रिक्त स्थान है। ऐसा भी है कि कोर्ट के निर्णय है जहां दीप मंडप पर दीपक प्रज्वलित करने की प्रथा का जिक्र है। लेखक का इस प्रसंग के कानूनी गुणदोष पर कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। प्रश्न इतना है कि जब जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं है तो फिर क्या मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध इस आदेश को महाअभियोग की कार्यवाही के द्वारा बिना निरस्त किये जस्टिस महाअभियोग की सजा में नौकरी से निकाला जा सकता? 56 पूर्व न्यायाधीशों ने अपने पत्र में इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुये कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश को इस प्रकार नौकरी ने निकालने की कार्यवाही करना सर्वथा अवैध, अन्धकृत और विवेकहीन है। नि:सन्देह इस प्रकार की कार्यवाही को न्याय संगत नहीं माना जा सकता यह अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीशों को Brow Beat करना ही कहा जावेगा। लोकतंत्र में न्यायाधीश को निर्भीक व स्वतंत्र विचार धारा का होकर संविधान व लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार एक सबल रक्षक के रूप में काम करना होता है। पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों

में विचार रखते हुये कहा है महाअभियोग के प्रतिवेदन में कोई भी संगत आधार प्रतिक्षित नहीं होते, क्योंकि महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिये। लोकतंत्र में न्यायालयों को स्वतंत्र, किसी बाहरी शक्ति के दबाव से दूर ही रहना चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही रूला ऑफ लॉ के लिये गम्भीर खतरा है। महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण है यह कार्यवाही तो न्यापालिका की गरिमा को बनाये रखने के हेतु ही की जाना अपेक्षित है। संविधान ने अपनी उद्देशिका में स्पष्ट घोषणा की है, भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण

कुछ समय से देश में देश के न्यायाधीशों पर कोर्ट की कार्यवाही सुनवाई करते समय वकीलों से प्रश्न पूछे जाने और जजों की टिप्पणी को इस प्रकार उद्धृत किया जाता है, जिससे यह कयास लगाया जाता है कि वे जजों को दबाव में लाना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने रोहिंन्या के प्रकरण पर टिप्पणी की थी।

प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिये दृढ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमों और आत्मार्पित करते हैं।

पूर्व न्यायाधीशों में सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व न्यायाधीश व हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश भी हैं। ये सब ही यशस्वी न्यायाधीश रहे हैं, अतः इन सबसे जब मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में उपरोक्त संदर्भ में कोई बात कही है तो उसका महत्व हमें समझाना होगा, यह विषय महाअभियोग लाने का तो नहीं हो सकता है।

कुछ समय से देश में देश के न्यायाधीशों पर कोर्ट की कार्यवाही सुनवाई करते समय वकीलों से प्रश्न पूछे जाने और जजों की टिप्पणी को इस प्रकार उद्धृत किया जाता है, जिससे यह कयास लगाया जाता है कि वे जजों को दबाव में लाना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने रोहिंन्या के प्रकरण पर टिप्पणी की थी। उसके साथ जस्टिस जॉय माल्या बागची भी थे। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कुछ गणमान्य लोगों को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति की थी, इस पर प्रतिक्रिया देते हुये माननीय न्यायाधीश ने एक अन्य केस में सुनवाई के समय कहा था कि वे टफ आदमी हैं कोई ऐसा नहीं समझे कि न्यायपालिका ऐसी क्रियाओं पर दबाव में आ जायेगी। जस्टिस बागची ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि "जजों द्वारा सवाल पूछने से रोकने का यह एक संगठित प्रयास है। वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश ने रोहिंन्या घुसपैठियों का रैड कारनेट (लाल कालीन) निष्ठाकर स्वागत करें"।

कई बार टिप्पणी के द्वारा न्यायाधीशगण समस्या को समझने का प्रयत्न करते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार कोर्ट का निर्णय नहीं माना जाना चाहिये, किन्तु ऐसी टिप्पणी को जज ही पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

इन सब परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में अदालतों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया जा रहा है। इसे सावधानी से रोकना और गम्भीरता से विरोध करना अतिआवश्यक है।

इसी क्रम में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा सोशल मिडिया को नियंत्रित करने के समाचार के विषय में कहा कि ऐसे कठोर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सोशल मिडिया पर यह टिप्पणी की कि सोशल मिडिया जब संदर्भ हटाकर ट्वीलिंग की जाने प्रवृति को अपनाता है, उसकी अन्वेदनी भी नहीं की जा सकती।

लोकतंत्र की मजबूती इस पर निर्भर है वहां पर न्यायिक स्वतंत्रता पर कोई भी समझौता नहीं है जैन धर्म के धर्मावलंबियों की एक प्रार्थना है, "रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, या कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग मेरा कभी न पथ डिगने पाये"।

इसका अर्थ है नयायाधीश निष्पक्ष हो विषय का ज्ञाता हो, केस की, जिसका उसे निर्णय करना है, उसके तथ्यों की पकड़ हो, जिसकी IntegrityMebkeâe से परे हो। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था:-

"धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतेऽवधीतु।" "Dharma protects those who protect it. Those who destroy Dharma gets destroyed as a consequence thereof."

क्या जस्टिस स्वामीनाथन ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो उपरोक्त मापदण्डों के विपरीत हो। फिर क्या उनके विरूद्ध महाअभियोग की असाधरण कार्यवाही की जावे?

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



वीर बहादुर सिंह

विज्ञान और तकनीकी विकास के स्तर को देखते हुए अब प्रतीत हो रहा है कि स्नातक कृषि शिक्षा में भी कुछ नवीन आयाम खुलने चाहिए अथवा शिक्षा प्रदान करने की कक्षा कक्ष की प्रणाली में कुछ परिवर्तन घटित हों। ऐसा इसलिए कि विषय वस्तु भार अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ चुका है। ऐसे में यदि अपरिमित संसाधन और विषय सामग्री का समावेश पाठ्यक्रम में होता रहे तो छात्र के लिए उसे आत्मसात करने के लिए समय कम पड़ सकता है, और अध्यापक के लिए कालांश की संख्या में बढ़ोतरी भी जरूरी हो जाती है। हमें याद है आरम्भ में स्नातक केवल दो वर्ष का पाठ्यक्रम ही था, बहुती विषय सामग्री ने सेमेस्टर पद्धति में चार सेमेस्टर, फिर छः और अब आठ सेमेस्टर तक पहुंचा दिया है। इसलिए छात्र और अध्यापक दोनों को राहत स्वरूप कुछ परिवर्तन जरूरी है। पाठक इस लेख के लेखक को कोसें नहीं, लेख में वर्णित व्यवस्था लेखक को राजस्थान में वर्षों कार्य के दौरान प्राप्त वृहत अनुभवों पर बलवती होती धारणा पर आधारित है। कृषि उच्च शिक्षा की एक परिवर्तित प्रणाली, जिसमें

महाविद्यालय बनाने और अध्यापकों को नियुक्ति से निजात मिलेगी। लेखक ने इस प्रणाली को बिना अन्य से विमर्च और सम्बाद किये स्वयं ही रूप देने का प्रयास किया है।

इस प्रणाली को उत्पन्न करने और मूर्तरूप देने में प्रदेश सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों पर सदैव आर्थिक दृष्टि से आंख बहाने का दृश्य मुख्य कारक रहा। कृषि शिक्षा को राजस्थान सरकार फिजूल का उपक्रम मानती रही है और इसीलिये कृषि उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार सदैव उदासीन, गैरजम्मेदार और कभी कभी विरोधी भी रही है। मेरी समझ से इसका मुख्य कारण योजना नियोजकों को कृषि के असंख्य पहलुओं पर उनकी सभी स्तरों पर अनिभिज्ञता और नासमझी ही है। प्रदेश के बहुत से अधिकारियों को अभी तक ज्ञात होगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में कृषि विषय भी एक विशेष शाखा के तौर पर पढ़ाया जाता था। जहाँ छात्र विज्ञान, शिक्षा कहीं अधिक धन परस्त और खर्चीली हो चुकी है। और जब सम्पूर्ण शिक्षा का भार सरकारों को वहन करना पड़े तो अधिकारियों के पसोंने छूटने लगजमी है। ज्ञान में अपार वृद्धि से शिक्षा के इतने अधिक आयाम हो चुके हैं कि उनको गिना मुश्किल है।

कृषि शिक्षा में भी अभूतपूर्व विकास विषय सामग्री के हिसाब से हुआ वहीं अनुसन्धान और एक्सटेंशन शिक्षा के नेशनल लेवल पर कई संस्थाएं स्थापित हो गयीं जिनमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई देहली प्रमुख है। इस लेख को लिखते समय दिनांक 14 दिसंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव की अखबारी खबर कि रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया को गति देकर नियुक्तियों की जायें। प्रश्न

का यह कि माध्यमिक स्तर की कृषि शिक्षा मेडिकल और अभियांत्रिक के पात्र बायोलॉजी एवं विज्ञान व गणित की भांति ही समानरूप से महत्वपूर्ण थी।

इतना कुछ भूमिका वर्णन करने के पश्चात् अब मुख्य विषय पर लौटना हूँ। हमें ज्ञात है कि पौराणिक काल में शिक्षा गुरु-शिष्य आधार पर ही दी जाती थी। उस काल में महाविद्यालय अथवा कक्षा कक्ष की कोई आवश्यकता न थी। शिष्य और गुरु बरगद अथवा अन्य किसी ऐसे ही छायादार वृक्ष के नीचे जमीन पर बैठ कर ज्ञान और संस्कारों का आदान-प्रदान करते थे। अधिक समय नहीं गुजरा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कुछ इसी भाँति शिक्षा पाई थी। वर्तमान की शिक्षा के संसाधनों को देखते हुए कल्पना की नहीं की जा सकती कि कालान्तर में पढ़ाई पेड़ या घासफूस की झोंपड़ पट्टी में होती थी। यह सही है कि विज्ञान और संसाधनों में उन्नति होने से शिक्षण संस्थाओं का रूप भी बदला है। फलस्वरूप आज की शिक्षा कहीं अधिक धन परस्त और खर्चीली हो चुकी है। और जब सम्पूर्ण शिक्षा का भार सरकारों को वहन करना पड़े तो अधिकारियों के पसोंने छूटने लगजमी है। ज्ञान में अपार वृद्धि से शिक्षा के इतने अधिक आयाम हो चुके हैं कि उनको गिना मुश्किल है।

कृषि शिक्षा में भी अभूतपूर्व विकास विषय सामग्री के हिसाब से हुआ वहीं अनुसन्धान और एक्सटेंशन शिक्षा के नेशनल लेवल पर कई संस्थाएं स्थापित हो गयीं जिनमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई देहली प्रमुख है। इस लेख को लिखते समय दिनांक 14 दिसंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव की अखबारी खबर कि रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया को गति देकर नियुक्तियों की जायें। प्रश्न

ये है जब सरकार ने नियुक्ति प्रणाली को शुरू ही नहीं क्या तो फिर गति किसको और फिर उनका निर्देश किसको है जबकि वे खुद ही सर्वसर्वा हैं। नियुक्ति का अधिकार भी सरकार के ही पास है। जनता को मूर्ख बनाने और एक सफूगा छोड़ने के अलावा ऐसा निर्देश कोई मायने नहीं रखता। पाठक इस बात पर चिंतन करें कि कक्षाओं में पढ़ाई कैसे हो रही है जब उचित अध्यापक ही नहीं हैं और पढ़ाई की निगरानी के लिए महाविद्यालय का प्रिंसिपल अथवा अधिष्ठाता भी महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले किसी भी विषय का नहीं है। न, पहली, क्योंकि बिना उचित विषय विशेषज्ञ के कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है? परीक्षा भी हो रही है और छात्र उत्तीर्ण भी हो रहे हैं, है न आश्चर्य?

इसका कारण, कृषि अनुसन्धान परिषद् ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार नोट्स नेट पर उपलब्ध करा रखे हैं। छात्र उन्हें ही अपने स्मार्ट फ़ोन में पढ़ते हैं इसलिए उन्हें सैद्धांतिक पढ़ने के लिए कक्षा और टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार श्योरी क्लासेज की गुल्थी तो सुलझती प्रतीत लग रही है फिर भी इन नोट्स में वर्णित विषय सामग्री को और अधिक ग्राह्य तथा विकसित किया जा सकता है। अब दूसरी यह कि प्रैक्टिकल कक्षाओं का क्या होता है? कृषि में ऐसे विषय भी हैं जिनमें प्रैक्टिकल खेतों, फार्म, नदियों, तालाबों, बनों, बांधों, और फसलें उगे हुए किसानों के खेतों पर कराये जा सकते हैं। अभी तो करोड़ों रुपये के महंगे प्रयोगशाला उपकरण वर्षों से भूल चाट रहे हैं और संभवतः अनेक जो खादुरन बेकार भी हो चुके हों? खोजबन करने पर मालूम हुआ कि प्रैक्टिकल तो विषय का टीचर नहीं

होते हुए कराये ही नहीं जा रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक ही नहीं है, कराये का टीचर हो लैब में जाकर कतिपय उपकरण दिखा कुछ बता देता है अधिक बताने के लिए उसके पास भी नॉलेज नहीं, उसे तो कालांश किसी प्रकार पूरा करना है। वह हो जाता है आखिर में उसका पारश्रमिक बना कर अदा कर दिया जाता है। लेखक चौंकि इस विषय पर अधिक गंभीर था तो अनेक व्यक्तियों से पूछ कर वांछित जानकारी जुटाना संभव हो सका। प्रदेश सरकार को कृषि अनुसन्धान परिषद् को वाले किसी भी चाहिए कि छात्रों को प्रत्येक विषय के विस्तृत विवरण नेट पर उपलब्ध अतः कक्षा में पढ़ाने के लिए किसी टीचर की नियुक्ति की जरूरत नहीं। भारी वेतन पर होने वाले खर्च से निजात मिलेगी।

अब केवल प्रैक्टिकल करने या कराने की बात शेष रहती है। मेरे पास विकल्प है लेकिन उसके लिए विचार-विमर्श सरकार के स्तर पर भी जरूरी है। सरकार के प्रशासन वर्ग को मैं सबसे अधिक शिक्षित, बुद्धिमान और विवेकशील मानता हूँ इसलिए इस विषय पर आगे मंथन वहां से भी अपेक्षित है। यदि यह प्रणाली कारगर हो गई तो प्रदेश सरकार के लिए तो वरदान साबित होगी और छात्र का समय बचेगा। रिक्त पदों और उन्हें भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आर्थिक दृष्टि से घन की अपार बचत होगी। सरकार की आर्थिक शक्ति भी सुदृढ़ हो जाएगी। जय कृषि जय किसान जय भारता

—प्रो.वीर बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता डी व् खेड़ा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि. विद्यालय, उदयपुर

राजस्थान उच्च शिक्षा बजट प्रस्ताव 2026-27



अशोक कुमार

राजस्थान के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उच्च शिक्षा में निवेश अनिवार्य है। बजट प्रस्तावों को केवल व्यय के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में पर्याप्त बजट आवंटन राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक मजबूत, समावेशी और विश्व स्तरीय प्रणाली में बदल सकता है।

राजस्थान की उच्च शिक्षा को संवराने में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का अमूल्य योगदान रहा है। विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने हेतु प्रदेश के ये उच्च शिक्षण संस्थान आधारस्तंभ हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान को लेकर अक्सर असमंजस और देरी की स्थिति बनी रहती है। अतः आगामी बजट में विश्वविद्यालयों के लिए एक स्थायी पेंशन कॉर्पस फंड का प्रावधान किया जाए ताकि कर्मचारियों को नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सके। यदि विश्वविद्यालयों में सामाजिक सुरक्षा, पेंशन का अभाव रहा, तो प्रदेश के मेधावी युवा अध्यापन के बजाय

लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र: सभी विश्वविद्यालयों में एक समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए फंडा। ये केंद्र एनहपी 2020 के अनुसार मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा, डिजिटल शिक्षण विधियों और शोध नैतिकता पर अनिवार्य प्रशिक्षण देंगे। शोध प्रस्ताहनों: शिक्षकों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ़रेंस में भाग लेने और उच्च गुणवत्ता के पीयर-रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशन के लिए प्रोत्साहन राशि

2. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सुधार:

कौशल-आधारित शिक्षा: कौशल विकास और इंटरशिप को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए बजट। इसके लिए एमएससी उद्योगों और एमएसएमइएस के साथ साझेदारी विकसित करने हेतु फंड।

अद्यतन प्रयोगशालाएँ: विज्ञान, इंजीनियरिंग, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने हेतु एक आधुनिकीकरण कोष।

1. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर: डिजिटल पहुँच का विस्तार: सभी सरकारी कॉलेजों को हाई-स्पीड इंटरनेट और वाई-फाई से लैस करने के लिए डिजिटल पहुँच मिशन। ई-संसाधन सब्सक्रिप्शन: सभी छात्रों और संकाय के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों (जैसे- स्कोपस) की सदस्यता लेने हेतु केंद्रीय फंडिंग। स्मार्ट क्लासरूम: 75 प्रतिशत से अधिक कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम (प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव बोर्ड) में बदलने के लिए विशेष परियोजना।

2. भौतिक बुनियादी ढाँचा: कॉलेज भवन और छात्रावास: दूरदराज के क्षेत्रों और छात्राओं के लिए नए छात्रावासों के निर्माण और पुराने भवनों के जीर्णोद्धार के लिए बड़ा बजट। विश्वविद्यालय शोध उपकरण: उच्च-स्तरीय शोध उपकरण जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्लस्टर आदि खरीदने के लिए एक शोध उपकरण खरीद निधि।

तीसरा- पहुँच, समानता और समावेशन : राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए वंचित समूहों तक पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है।

1. छात्राओं के लिए विशेष

योजनाएँ:

“उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना”: ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए नकद प्रोत्साहन या ट्यूशनियन फीस में पूर्ण छूट।

सुरक्षित परिवहन: छात्राओं को कॉलेज तक पहुँचाने के लिए सुरक्षित और सब्सिडीयुक्त परिवहन सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बजट।

2. वंचित समूहों के लिए समर्थन: विशेष कॉमिंग: एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे- एनईट, यूपीएससी, आरपीएससी) की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग सेंटर स्थापित करने और चलाने के लिए फंड।

डिव्यांगन सहायता: एनहपी 2020 के अनुसार, दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा-मुक्त परिसर, विशेष शिक्षण सामग्री और सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए अलग कोष।

चौथा- अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालयों को ज्ञान सृजन के केंद्र में बदलना।

पाँचवा- शासन और जवाबदेही संस्थागत प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

डेटा प्रबंधन प्रणाली: समय पर और सटीक डेटा संग्रह के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने हेतु बजट। यह एआईएसएलएच रिपोर्ट में देरी जैसी समस्याओं से बचने में मदद करेगा।

संस्थागत स्वायत्तता प्रोत्साहन: अच्छा प्रदर्शन करने वाले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन

वित्तीय लेखापरीक्षा: आवंटित बजट के प्रभावी और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमित वित्तीय और शैक्षणिक लेखापरीक्षा के लिए व्यवस्था। विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में किया गया निवेश राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की कुंजी है।

विज्ञान और एआई तकनीक के लिए बजट प्रस्ताव

इन प्रस्तावों को तीन प्रमुख स्तंभों में विभाजित किया जा सकता है: बुनियादी ढाँचा, मानव पूंजी , और अनुसंधान एवं नवाचार।

प्रथम- बुनियादी ढाँचा और डिजिटल क्षमता निर्माण

1. उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाएँ:

एआई सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर: राज्य के शीर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों (जैसे- आइआईटी, एनआईटी, या प्रमुख राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज) में एक या दो उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए फंड।

मांग: जीपीयू सर्वर, शीतलन प्रणाली, और इनके संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समर्पित वार्षिक बजट।

2. अटल टिकरिंग लैब और एसीटीएम लैब का विस्तार:

उच्च शिक्षा में अटल लैब: स्कूली शिक्षा में सकलतापूर्वक लागू एटीएल मॉडल को उच्च शिक्षण संस्थानों (विशेषकर पॉलिटेक्निक और छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजों) में एडवांस्ड एसीटीएम लैब के रूप में विस्तारित करने हेतु बजट।

मोबाइल विज्ञान वैन: ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सुसज्जित मोबाइल विज्ञान और एआई लैब वैन की खरीद और संचालन के लिए फंड।

द्वितीय- मानव पूंजी और कौशल विकास और विज्ञान के लिए कुशल कार्य बल तैयार करना

1. एआई उत्कृष्टता केंद्र: राज्य एआई केंद्र: कम से कम चार क्षेत्रीय एआई उत्कृष्टता केंद्र (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) स्थापित करने के लिए पर्याप्त आवंटन, जैसा कि केंद्र सरकार के इश्टया एआई मिशन में भी प्रस्तावित है (जिसके लिए 10,372 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं)।

फोकस क्षेत्र: इन केंद्रों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष क्षेत्रों (जैसे एग्री-एआई, हेल्थ-एआई, गवर्नेंस-एआई) पर केंद्रित होना चाहिए।

2. संकाय अपस्कीलिंग और भर्ती:

एआई संकाय फैलोशिप: इंजीनियरिंग और विज्ञान कॉलेजों के शिक्षकों को एआई/एमएलए नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए एआई संकाय फैलोशिप कार्यक्रम शुरू करने हेतु बजट।

विषय-विशेषज्ञों की भर्ती: एआई, डेटा साइंस, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में उद्योग विशेषज्ञों को अल्पाकालिक या विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्त करने के लिए आकर्षक वेतन पैकेज

का प्रावधान।

3. कौशल आधारित पाठ्यक्रम: डिजिटल साक्षरता और एआई प्रमाणन: सभी स्नातक पाठ्यक्रमों (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में बुनियादी डिजिटल साक्षरता और एआई के नैतिक उपयोग पर एक अनिवार्य प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पाठ्यक्रम विकास और प्रशिक्षण लागत हेतु बजट।

तीसरा- अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

ज्ञान सृजन और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को बढ़ावा देना।

1. अनुसंधान अनुदान : एआई मुख्यमंत्री और विज्ञान शोध ग्रांट: राज्य के शोधकर्ताओं को उच्च प्रभाव वाले और सामाजिक रूप से प्रासंगिक शोध के लिए बड़ा अनुदान प्रदान करने हेतु एक बजट और समर्पित राज्य शोध निधि का निर्माण।

धीमा-आधारित अनुदान: विशेष रूप से राजस्थान की समस्याओं (जैसे जल प्रदूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, मरुस्थलीकरण) को हल करने वाले शोध के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन।

2. नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन:

डीप-टेक इन्क्यूबेशन केंद्र: विज्ञान और एआई में काम कर रहे स्टार्टअप के लिए डीप-टेक इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें पहले वर्ष में 5 लाख तक का ग्राफ-ऑफ-कॉस्टेड अनुदान देने के लिए बजट।

पेटेंट और बौद्धिक संपदा सहायता: विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और स्टार्टअप द्वारा फाइल किए गए पेटेंट की लागत (आवेदन शुल्क, कानूनी शुल्क) को कवर करने हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता।

3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदारी: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों को अपने सीएसआर फंड का एक हिस्सा विज्ञान और एआई में शोध एवं विकास पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नीतिगत और बजटीय प्रोत्साहन देना। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राजस्थान को केवल प्रौद्योगिकी का उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि एआई और विज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी निमाता बनाना होना चाहिए।

—अशोक कुमार, पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर



पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज देव पितृकाय अमावस्या, वकुला अमावस्या है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ-अमृत 8:32 से 11:06 तक, शुभ 12:24 से 1:41 तक, चर 4:16 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:33 तक

राशिफल

शुक्रवार 19 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, शुल योग दिन 3:47 तक, चतुष्पद करण सायं 6:06 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:51 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज देव पितृकाय अमावस्या, वकुला अमावस्या है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ-अमृत 8:32 से 11:06 तक, शुभ 12:24 से 1:41 तक, चर 4:16 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:33 तक

मेघ अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ-मांगलिक

बीकानेर के पीबीएम में कैंसर मरीज को गलत ब्लड चढ़ाया, तबीयत बिगड़ी

पीबीएम हॉस्पिटल के आचार्य तुलसी कैंसर विंग में मरीज भंवरी देवी को दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाया

बीकानेर, (निर्स)। पीबीएम हॉस्पिटल के आचार्य तुलसी कैंसर विंग में एक मरीज को गलत ब्लड चढ़ा दिया। यहां मरीज भंवरी देवी (75) को दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना के वक्त कैंसर विंग में एक डॉक्टर और दो नर्सिंग स्टाफ मौजूद थे। जब भंवरी देवी को गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा था, तभी वहां मौजूद एक परिजन की नजर ब्लड यूनिट पर लिखे ग्रुप पर पड़ी। परिजन ने तुरंत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को मौके पर बुलाया। तुरंत इलाज शुरू किया गया, जिससे महिला की हालत संभल गई।

परिजनों के अनुसार, भंवरी देवी को खून की कमी के चलते भर्ती किया गया था। उनका ब्लड ग्रुप ए प्लस है। पहले 'ए' पॉजिटिव ब्लड की एक यूनिट चढ़ाई गई। इसके बाद दूसरी यूनिट की जरूरत बताई गई। परिजन ब्लड बैंक से एक और यूनिट लेकर आए, लेकिन वहां से गलत ग्रुप (बी पॉजिटिव) का ब्लड दे दिया गया। कैंसर विंग के नर्सिंग स्टाफ ने बिना

- जब भंवरी देवी को गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा था, तभी वहां मौजूद एक परिजन की नजर ब्लड यूनिट पर लिखे ग्रुप पर पड़ी**

- परिजन ने तुरंत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को मौके पर बुलाया तुरंत इलाज शुरू किया गया, जिससे महिला की हालत संभल गई**

- कैंसर विंग में भंवरी देवी नाम की दो महिला मरीज भर्ती थीं, जिनके पति के नाम अलग-अलग थे, दोनों मरीजों को खून चढ़ाया जाना था**

- गलत खून चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट मांगने पर सरकार को रिपोर्ट भेजी गई**

क्रॉस चेक किए वही ब्लड मरीज को चढ़ा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।

जानकारी के अनुसार कैंसर विंग में भंवरी देवी नाम की दो महिला मरीज भर्ती थीं, जिनके पति के नाम अलग-अलग थे। दोनों मरीजों को खून चढ़ाया जाना था। नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की पहचान करते समय पति का नाम और अन्य पहचान विवरण नहीं देखे। दूसरी

भंवरी देवी के लिए मंगवाया गया ब्लड पहली भंवरी देवी को चढ़ा दिया। गलत ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होते ही

करीब 30 सेकेंड के भीतर मरीज की हालत बिगड़ने लगी। मरीज को घबराहट और बेचैनी होने लगी। तभी वहां मौजूद परिजन की नजर ब्लड यूनिट और मरीज के ब्लड ग्रुप पर पड़ी। परिजन ने तुरंत डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को मौके पर बुलाया और

ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुकवाया।

घटना की शिकायत सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा से की गई। कुछ ही देर में प्रिंसिपल खुद कैंसर विंग में पहुंच गए। कैंसर विंग के एचओडी डॉ. सुरेंद्र बेनीवाल भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही।

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही रात में मौके पर पहुंचे थे। पेशेंट की हालत फिलहाल बिल्कुल स्थिर है। उसका हीमोग्लोबिन 4.4 ग्राम प्रतिशत था, जिस कारण रात में उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कुछ समस्या सामने आई।

डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सभी विभागों के साथ बैठक कर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े सरकारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने वाले नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर या टेक्नीशियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विभागीय और प्रिंसिपल स्तर पर जांच

कमेटी गठित कर दी गई है, जो तीन दिन में रिपोर्ट देगी। गलत खून चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट मांगी है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है।

इस घटना के बाद भाजयुमो शहर अध्यक्ष वेद व्यास अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। उन्होंने पीबीएम अधीक्षक डॉ. बी.सी. शीया से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। बाद में जब प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे तो उनके सामने भी लापरवाही को लेकर अपोजिट दर्ज कराई गई।

गुरवार सुबह भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़ुतिया और भाजयुमो शहर अध्यक्ष वेद व्यास मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा के कार्यालय पहुंचे और घटना को लेकर विरोध दर्ज करवाया। नेताओं ने आरोप लगाया कि अस्पताल में सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों से बाहर से इंजेक्शन, सुलुकोज और कैनुला तक मंगवाए जा रहे हैं।

दुकान का शटर काट 17 लाख की ज्वैलरी ले गए चोर

अलवर, (निर्स)। अलवर शहर के एनईबी थाना इलाके में 60 फीट रोड के पास रामनगर कॉलोनी कट पर स्थित कृतिका ज्वैलर्स पर अज्ञात चोरों ने रात के सत्राते में सेंध लगाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान का शटर काटकर अंदर घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। सुबह के समय पड़ोसी दुकानदार की नजर टूटी हुई शटर पर पड़ी, तो उन्होंने फौन दुकान मालिक को खबर दी और पुलिस को सूचित किया। एनईबी थाने के एसएचओ दिनेश चंद मीणा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में दुकान मालिक ने बताया कि चोर करीब 7० ग्राम सोना और लगभग 4.5 किलो चांदी चोरी कर ले गए। चोरी गए माल की अनुमानित

- पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली**

कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद से ज्वैलर्स सदमे में है। कृतिका ज्वैलर्स के मालिक बंटी ने बताया कि वह बुधवार शाम दुकान बंद कर सूर्य नगर स्थित अपने घर चले गए थे। सुबह पड़ोसी दुकानदार के जरिए चोरी की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी कैमरे में चोरों की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात चोरों की तलाश जारी है।

अलवर में नौ साल की बच्ची की हत्या

अलवर, (निर्स)। अलवर में नौ साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। मर्डर का शक पिता पर ही जताया जा रहा है। पुलिस बच्ची के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र का गुरवार सुबह आठ बजे का है।

एसपी शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि 9 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था। बच्ची गुरुवार सुबह 8 बजे घर से बकरियां छोड़ने के लिए जंगल में गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। बच्ची के शरीर पर खरोंच के निशान भी है।एसएएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। बच्ची के ताऊ और ममेरे भाई ने अलग-अलग शिकायत दी है। ममेरे भाई ने बच्ची के पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ताऊ ने हत्या की आशंका जताई है।

बच्ची के ताऊ ने बताया कि जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की। अक्सर बच्ची बकरियां छोड़ने के बाद कुछ

- मर्डर का शक पिता पर ही जताया, पुलिस पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था**

ही देर में घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज नहीं आई तो उसकी तलाश की। इसी दौरान झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना मिली। बच्ची चार बहन-भाइयों में तीसरे नंबर की थी।

प्रारंभिक जांच में बच्ची के गले और शरीर पर खरोंच के निशान मिले हैं, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्ची की मां पीहर गई हुई थी। पुलिस आफसरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डीडवाना, (निर्स)। डीडवाना में लोगों को उकसाकर और दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में डीडवाना पुलिस ने लालचंद डेविड नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने 15 से 2० लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और खासतौर पर गरीब, पिछड़े व कम शिक्षित वर्ग के लोगों को निशाना बनाया।

मामले को लेकर पुलिस उप अधीक्षक जेदू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डीडवाना निवासी राहुल द्वारा डीडवाना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें लालचंद डेविड पर लोगों को बहला-फुसलाकर और मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया गया था।

रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपों की पुष्टि होती चली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लालचंद डेविड मूल रूप सेहिंदू था। करीब आठ वर्ष पहले उसकी माता के बीमार होने के दौरान वह ईसाई पादरियों के संपर्क में आया। उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की और उसकी माता के स्वस्थ होने के बाद इसे चमत्कार मानते हुए उसने ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद से वह ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार



आरोपी लालचंद डेविड

था। करीब आठ वर्ष पहले उसकी माता के बीमार होने के दौरान वह ईसाई पादरियों के संपर्क में आया। उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की और उसकी माता के स्वस्थ होने के बाद इसे चमत्कार मानते हुए उसने ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद से वह ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार

1 5 साल पुराने हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा शर्मा ने 15 साल पुराने हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी भागीरथ, किशोर उर्फ किशोरसिंह और रामप्रकाश उर्फ गुट्टा को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1.56 लाख जुर्माने की सजा दी है।

मामला करीब पंद्रह साल पुराना है। 28 फरवरी 2०10 को होली के दिन जोधपुर के पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र के खांटा गांव में पालड़ी चौराहे पर शराब के पैसे को लेकर हुए विवाद में दिनेश की चाकू और हाथ की टूटी बोटलों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मयंक रंकावत ने पक्ष रखा।

परिवादी कानाराम ने पीपाड़ शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दफ्तरी रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी 2०10 की

- पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र के खांटा गांव में पालड़ी चौराहे पर शराब के पैसे को लेकर हुए विवाद में दिनेश की चाकू और कांच की टूटी बोटलों से हमला कर हत्या कर दी गई थी**

शाम करीब 7:45 बजे ग्राम खांटा के पालड़ी चौराहे पर स्थित शराब की दुकान पर राजूराम पुत्र केसाराम सेल्समैन था। उस समय दिनेश, रामकरण, सांवरराम आदि खड़े थे, तभी पूर्व नियोजित तैयारी के साथ एकराय होकर एक बोलेंगो जीप में सवार होकर आए 8-9 लोग दुकान पर आए। इनमें से रामनिवास मुंडेल, माधुराम, रामप्रकाश, किशोर, भागीरथ और इनके साथ 3-4 अन्य व्यक्तियों ने दुकान पर आकर शराब मांगी। शराब के पैसे मांगने पर उन लोगों ने यह कहकर मना कर दिया कि वे पैसे नहीं देंगे। वे जबर्दस्ती शराब की बोटलें उठाकर दुकान के भीतर घुसकर गल्ले

उर्फ राजेंद्र के शरीर को जगह-जगह चाकूओं से छलनी कर दिया। सांवरराम के हिचकी पर चाकू की चोट आई। इस हमले से दिनेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा शेष सभी गायब हो गए। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इनमें मुख्य आरोपी तीनों भाई (भागीरथ, किशोर उर्फ किशोरसिंह और रामप्रकाश उर्फ गुट्टा) के अलावा उनके पिता माधुराम और एक अन्य साथी रामनिवास भी नामजद थे। ट्रायल के दौरान माधुराम और रामनिवास की मौत हो गई। इसी कारण उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई।

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 24 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपियों ने मिलकर

दिनेश, राजूराम, रामकरण व सांवरराम की हत्या करने के इरादे से धारदार हथियार, चाकू व कांच की टूटी हुई बोटलों से हमला किया।

कोर्ट ने कहा कि प्रकरण के सभी तथ्यों व परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपिताण को दोषसिद्ध कर दंडित किया जाना न्यायोचित है। इसके लिए तीनों दोषियों को धारा 302/34 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माना, धारा 3०7 (हत्या का प्रयास) के तहत 1० वर्ष कठोर कारावास और 5०-5० हजार रुपए जुर्माना, धारा 325 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास और 3-3 हजार रुपए जुर्माना, धारा 324 के लिए 3 वर्ष कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माना और धारा 323 के तहत 1 वर्ष कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

सांवलियाजी सेठ के भंडार से 12.10 करोड़ रुपये निकले



भंडार गिनती में मंदिर बोर्ड अध्यक्ष वैष्णव एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मंडफिया, (निर्स)। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थस्थल भागवान श्री सांवलियाजी सेठ मंडफिया के दरबार का विशाल भंडार गुरुवार चतुर्दशी को मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव व अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मंदिर की मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रभा गौतम की उपस्थिति में खोला गया।

मंदिर बोर्ड अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि चतुर्दशी को खोले गए भंडार

- भंडार से बची राशि की गणना एवं भंडार से निकले सोने-चांदी का तोल होना बाकी**

हुए उन्होंने ने बताया कि भंडार से बची राशि की गणना एवं भंडार से निकले सोने-चांदी का तोल होना बाकी है। मंदिर कार्यालय में विभिन्न भक्तों द्वारा भेंट किए गए सोने-चांदी का तोल एवं

भक्तों द्वारा भेंट रुपयों की गिनती होना भी शेष है। इस मौके पर मंदिर मंडल की ओर से यात्रियों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। भंडार गिनती में मंदिर बोर्ड सदस्य पवन तिवारी, रामलाल गुर्जर, हरिराम गाडरी, किशनलाल अहिरा, लेखाधिकारी राजेंद्र सिंह, मंदिर प्रभारी भेरू गिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह राजवत सहित मंदिर के चुनिंदा कर्मचारी एवं बैंकों के कर्मचारी उपस्थित थे।

यूआईटी लॉटरी मामले में एईएन को एपीओ किया

भीलवाड़ा, (निर्स)। यूआईटी लॉटरी मामले में विवादों में घिरे यूआईटी के सहायक अभियंता (वर्गएन) रविश श्रीवास्तव को एपीओ कर दिया गया, हालांकि इसके पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। वहीं लॉटरी के खिलाफ गठित संघर्ष समिति ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है।

नगरीय विकास विभाग के सरकारी आदेश के अनुसार, भीलवाड़ा में तैनात सहायक अभियंता रविश श्रीवास्तव का तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया गया है। प्रशासनिक कारणों से उन्हें अभी कोई नई जिम्मेदारी (पोस्टिंग) नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें जयपुर सचिवालय (हेडक्वार्टर) भेज दिया गया है। जब तक अलग आदेश नहीं आता, उन्हें जयपुर के नगर विकास विभाग में अपनी हाजीरी देनी होगी। श्रीवास्तव यूआईटी की ऑन लाइन लॉटरी में मुख्य सूत्रधार थे और उन्हीं के

द्वारा इस लॉटरी को संपादित करवाया गया था। लॉटरी में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विगत 2 महीनों से भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। भीलवाड़ा की जनता के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद यूआईटी के अधिकारियों ने भी ऑनलाइन प्रक्रिया में टेक्निकल एरर की बात को स्वीकार किया था। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मामले में जांच और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन सख्त एक्शन नहीं हो पाया। इस संबंध में सरकार के दो साल के जश्न को लेकर भीलवाड़ा आए डिप्टी सीएम और जिले के प्रभारी प्रेमचंद वैरवा के समक्ष संघर्ष समिति के संयोजक विजयपाल सिंह ने दस्तावेजों के साथ कार्यवाही की मांग उठाई, उसके बाद विवादों में घिरे यूआईटी एईएन रविश श्रीवास्तव को एपीओ कर दिया गया।

20 को सीएम के मांडलगढ़ दौरे की तैयारियां तेज

भीलवाड़ा, (निर्स)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 20 दिसंबर को प्रस्तावित मांडलगढ़ दौरे को लेकर प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू द्वारा कार्यक्रम स्थल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल भी साथ मौजूद रहे और तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

विधायक खंडेलवाल ने जनसभा में अधिक से अधिक आमजन को परिवादी के लिए जनसहभागिता महत्वपूर्ण है और इसके लिए व्यापक स्तर पर समन्वय किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने मंच, बैठक व्यवस्था,

- जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू व विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल ने कार्यक्रम स्थल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया**

यातायात, पार्किंग, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण जैन सहित संबंधित विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बीस हजार की रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर, (निर्स)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की (विशेष इकाई) जोधपुर टीम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना राजीव गांधी नगर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कांस्टेबल भविष्य कुमार को बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में पुलिस उप निरीक्षक फरार हो गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की (विशेष इकाई) जोधपुर को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके गांव चौखा में एक कब्जाशुदा किराये के मकान में रहता है। मकान को लेकर मकान मालिक भभुताराम एवं सागर गहलोत के बीच विवाद चल रहा है। जिसके चलते सागर गहलोत ने भभुताराम व परिवादी के पुत्र के खिलाफ पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में मामला दर्ज करवाया है। जहां जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक प्रेमनाथ व कांस्टेबल भविष्य कुमार द्वारा

- मामले में पुलिस उप निरीक्षक फरार, एसीबी की टीम तलाश कर रही है**

परिवादी को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में बुला कर सागर गहलोत को धमकाने का आरोप लगाकर मुकदमे पर परिवादी का भी मामला उसके फंसाने एवं गिरफ्तार करने की धमकी देकर मुकदमे से नाम हटाने की एवज में तीस हजार रुपये की रिश्वत की मांग रहे हैं, जिस पर एसीबी जोधपुर (एसयू) टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई करते हुए पुलिस कांस्टेबल को भविष्य कुमार को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के सामने परिवादी की गाड़ी में बैठकर बीस हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है और वहीं पुलिस उप निरीक्षक प्रेमनाथ एसीबी कार्यवाही की भनक लगने से मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत

जैसलमेर, (निर्स)। जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के सुभार मंडी रोड पर गुरुवार को एक सड़क हादसा हो गया। कृषि उपज मंडी के पास एक तेज रफ्तार निजी बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक को करीब 5० मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गई। इस भयावह मंजर में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर व कंडक्टर मौके से बस को छोड़कर फरार हो गए। मोहनगढ़ पुलिस ने अनिल विश्नोई के शव को हॉस्पिटल भिजवाया और बस को जब्त कर ड्राइवर कंडक्टर की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, बस मोहनगढ से अनूपगढ़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान सुभार मंडी रोड पर सामने से आ रही बाइक को बस ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान अनिल कुमार विश्नोई (3० वर्ष) पुत्र राकेश कुमार विश्नोई, निवासी ग्राम पंचायत जवाहरनगर, पुलिस थाना पीटीएम के रूप में हुई है।

रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौर ऊर्जा व बैटरी स्टोरेज की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

जयपुर, 18 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारागत 2 वर्षों में लिए गए निर्णयों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। साथ ही, किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक ली तथा माँग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने के लिए स्थाई कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय एवं ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों के लिये पर्याप्त और निर्राधं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विद्युत आपूर्ति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य में विद्युत आपूर्ति

में आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदार कार्मिकों और अधिकारियों की फील्ड विजिट में वृद्धि के लिए निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में बिजली की मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने की स्थायी कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने

अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योजना के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने ऊर्जा विभाग को प्रदेश में बैटरी स्टोरेज के साथ ही, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” के संचालन में प्रगति लाने के

लिए भी निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री को ऊर्जा विभाग की ओर से प्रजेेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की जानकारी दी गई। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

‘इंडिगो का बुरा समय बीत चुका है’

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्क्स ने गुरुवार को कहा कि बुरा समय बीत चुका है और 19 साल पुरानी विमान सेवा कंपनी को सिर्फ संकट के “तीन दिन” के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए।

एल्क्स ने कर्मचारियों के नाम जारी एक वीडियो संदेश में, कठिन समय में साथ देने के लिए कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “बुरा समय अब पीछे छूट चुका है।” कंपनी आज 2,200 उड़ानों का परिचालन कर रही है। यह टिमवर्क का नतीजा है।”

‘नारी सशस्त्रीकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सकात्मक अस्तर या गुंजाइश पैदा करने की स्थिति में नहीं होता। पीके यह बात समझते ही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था?

राहुल गांधी की तुलना में पीके का तात्कालिक प्रियंका के साथ बेहतर रहा है। जब उन्हें 2०17 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को चुनावी रणनीति सभालने को कहा गया था, तब पीके की पहली पसंद प्रियंका को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की थी। वर्ष 2०22 में भी, जब पीके ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रस्तुतियाँ दी थीं, उस समय, खबरों के मुताबिक, प्रियंका इस पक्ष में ज्यादा थीं कि उनसे पार्टी में शामिल होने का अनुरोध किया जाए।

पीके अपने करियर को इस तरह परिभाषित करते हैं—दस साल वर्ल्ड बैंक में, दस साल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में और अब दस

साल बिहार की स्थिति सुधारने के लिए। ‘एकला चालो’ के अपने घोषित रास्ते से किसी भी तरह का हटना उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या के समान होगा।

समझा जाता है कि व्यावहारिक सोच रखने वाले पीके ने प्रियंका के साथ हुई इस मुलाकात में, अनौपचारिक रूप से और बिना किसी पारिश्रमिक के, अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है।

राजनीति की राह अनिश्चित होने के कारण, पीके का मानना ​​​​है कि मौजूदा निराशाजनक हालात के बावजूद, कांग्रेस की किस्मत फिर से पलट सकती है। जेएसपी सूत्रों के अनुसार, प्रियंका को उन्होंने यह सलाह भी दी है कि देश की राजनीति में बढ़ते लैंगिक रुझान को देखते हुए, उन्हें पार्टी के कामकाज में और अधिक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए, ताकि पिछले वर्षों में राहुल के खिलाफ चलाए गए नकारात्मक प्रचार को संतुलित किया जा सके।

‘महबूबा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नीतीश कुमार ने इस सप्ताह को शुरूआत में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर का बुकी खींच कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। वह महिला डॉक्टर अपनी नियुक्ति पत्र लेने आई थीं। अब्दुल्ला ने कहा, “आगर (बिहार) के मुख्यमंत्री को उसे (मुस्लिम महिला) आदेश सौंपना नहीं चाहते थे, तो वे उसे अलग रख सकते थे। लेकिन, उसे इस तरह से अपमानित करना पूरी तरह गलत है।”

सरिस्का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
रेंजर शंकर सिंह ने बताया, आग करीब 1०0 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैल गई थी, लेकिन आग लगने का कारण पूरी तरह सामने नहीं आया है। एक युवक जंगल में मिला है, जिसने अलाव तापने की बात कही है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आता है।

‘ अगर केरल में जीतना है ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
इसका उत्तर है, क्या काम? असल में उनके पास या तो बहुत कम काम है या कोई काम ही नहीं है। अधिकांश राज्य के फैसले के.सी. वेणुगोपाल द्वारा ही लिए जाते हैं।

और बिना उनके “ओके” के, वे कोई निर्णय नहीं ले सकते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने, पंजाब के एआईसीसी महासचिव हैं, वेणुगोपाल की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेते।

नेताओं का कहना है कि पंजाब एक समृद्ध राज्य है, जिसमें बहुत पैसा है, और वेणुगोपाल एक ऐसा समूह नियंत्रित करते हैं, जो केवल उन्हें जवाब देता है।

राजस्थान के प्रभारी रंधावा भी इस समूह का हिस्सा हैं और रंधावा के माध्यम से वेणुगोपाल राजस्थान को नियंत्रित करते हैं।

रंधावा के अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और सीएलपी नेता टीकाराम जुली के साथ करीबी रिश्ते हैं।

जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी इस समूह द्वारा की गई है, जिससे राज्य नेतृत्व के दिल्ली लाना आवश्यक है, ताकि राजस्थान में एक नए नेता के लिए जगह बन सके।

स्रोतों का कहना है कि नया नेता सचिन पायलट नहीं हो सकता, क्योंकि वेणुगोपाल डोटासरा को बढ़ावा दे

- राजस्थान में प्रभारी रंधावा यह भूमिका निभा रहे हैं तथा वे अशोक गहलोत, डोटासरा व जुली को साथ लेकर राजस्थान में कांग्रेस संगठन चला रहे हैं।**

- गहलोत किसी तरह अपना पुनर्वास चाहते हैं तथा वेणुगोपाल अब उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाना चाहते हैं और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वेणुगोपाल तर्क दे रहे हैं कि गहलोत को दिल्ली भेजना इसलिए भी जरूरी है, जिससे नये नेताओं को काम करने का पूरा खुला मौका मिले और इस तर्क का मतलब यह भी नहीं कि नया नेता सचिन पायलट ही होंगे। आजकल रंधावा डोटासरा पर ज्यादा मेहरबान हैं।**

- यह व्यंग्य भी सुनाई दे रहा है कि जिस तरह वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को सम्मोहित कर रखा है, शायद केरल की जनता को भी सम्मोहित कर लें और कांग्रेस केरल में जीत कर सरकार बना ले।**

ओवरटाइम काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में लाया जा सके, भले ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ खुली बगावत की थी।

वेणुगोपाल द्वारा प्रचारित की जा रही लाइन यह है कि गहलोत को दिल्ली लाना आवश्यक है, ताकि राजस्थान में एक नए नेता के लिए जगह बन सके।

स्रोतों का कहना है कि नया नेता सचिन पायलट नहीं हो सकता, क्योंकि वेणुगोपाल डोटासरा को बढ़ावा दे

रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वेणुगोपाल, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कमजोर हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं और उनका प्रभाव पूरे भारत में है और केवल वे ही कांग्रेस के लिए केरल जीत सकते हैं।

इस समय चर्चाएं हैं कि वाम मोर्चा सत्ता में लौटने की तैयारी में है, लेकिन जैसे के.सी. वेणुगोपाल ने अपनी जादूगरी से राहुल का विश्वास हासिल किया, वैसे ही वह केरल में भी जादू कर सकते हैं।

प्र.मंत्री मोदी ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ से सम्मानित

मस्कट, 18 दिसम्बर। ओमान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने गुरुवार को मस्कट में प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा।

मोदी दो दिन की यात्रा पर ओमान

- यह ओमान का सर्वोच्च सम्मान है और सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने मस्कट में मोदी को इस सम्मान से नवाज़ा।**

गए हुए हैं। इससे पहले मोदी को इथियोपिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था।

मोदी और सुल्तान अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीडीपीए) पर हस्ताक्षर भी किए।

प्र.मंत्री मोदी ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ से सम्मानित

मस्कट, 18 दिसम्बर। ओमान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने गुरुवार को मस्कट में प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा।

- यह ओमान का सर्वोच्च सम्मान है और सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने मस्कट में मोदी को इस सम्मान से नवाज़ा।**

गए हुए हैं। इससे पहले मोदी को इथियोपिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था।

मोदी और सुल्तान अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीडीपीए) पर हस्ताक्षर भी किए।

मनरेगा खत्म करने की साजिश का सख्त विरोध करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार का विकसित भारत जी राम जी बिल गरीब विरोधी है

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा है कि "विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (संशोधन) विधेयक 2०25 गरीब विरोधी है और यह सरकार की मनरेगा को खत्म करने की रणनीति है, जिसका सख्त विरोध किया जाएगा।

वाड़ा ने लोकसभा में वीबी-जी-राम-जी (संशोधन) विधेयक 2०25 के पारित होने के बाद, संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि "यह बिल गरीबों के खिलाफ है। वे और उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेंगी। इस विधेयक से आने वाले

लाल किला बम विस्फोट मामले में एक और मुख्य आरोपी गिरफ्तार

आरोपी यासिर अहमद दार शोपियां का निवासी है

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 1० नवंबर को हुए कार विस्फोट मामले में एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

इस मामले में गिरफ्तार होने वाला नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस कार

नीति आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन्होंने मानव-निर्मित फाइबर का उदाहरण दिया। वैश्विक कपड़ा व्यापार का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा इसी सेगमेंट में केंद्रित होने के बावजूद, कच्चे माल और जरूरी इनपुट्स पर सख्त नीतियों की वजह से भारत का वैश्विक स्तर पर बड़ा खिलाड़ी बनने का सपना कमजोर हो रहा है। सिर्फ दो बड़े घरेलू आपूर्तिकर्ता 35 से 4० प्रतिशत तक ऊँची कीमत वसूल पा रहे हैं और आयात लगभग बंद है। ऐसे में नीचे की कड़ी के निर्माता कीमतों में प्रतिस्पर्धा और निर्यात, दोनों अवसर को देखते हैं।
कांत के अनुसार, इसका सीधा असर रोजगार सृजन पर पड़ता है, खासकर ऐसे क्षेत्र में, जो श्रम-प्रधान हैं।
कांत ने हाल ही में कुछ क्यूसीओ वापस लिए जाने का स्वागत किया, लेकिन अपना रुख साफ रखा। उनके अनुसार, ऐसे आदेश कभी भी इनपुट्स, मध्यवर्ती उत्पादों या पुर्जों पर लागू नहीं होने चाहिए। उनका कहना है कि इस सीमा को बार-बार पार किया गया है, जिससे क्वालिटी एश्योरेंस टूल संरक्षणवाद की दीवार में बदल गया है।

इस सवाल पर, कि क्या क्यूसीओ क्लिकुल भी जायज़ है, कांत ने उन्हें सीधे तौर पर पूरी तरह खारिज नहीं किया। अंतिम उत्पादों के लिए, उन्होंने कहा, हर सामान के लिए उन पर केस दर केस के आधार पर विचार किया जा सकता है, बशर्तें सही एनालिसिस, पारदर्शिता और

- एनआईए ने यासिर को नई दिल्ली से यूएपीए तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया है।**

बम विस्फोट के पीछे की साजिश में डार की सक्रिय भूमिका का खुलासा हुआ है। वह इस साजिश का एक सक्रिय भागीदार था और उसने आत्मघाती अभियानों को अंजाम देने के लिए कसम खाई थी।

जांच से यह भी पता चला है कि डार इस मामले के अन्य आरोपियों के साथ निकट संपर्क में था, जिनमें बमबारी को अंजाम देने वाला मृत अपराधी उमर नबी और मुफ्ती इफ्रान शामिल हैं।

केंद्रीय एजेंसी विभिन्न राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस आतंकी

विपक्ष के भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पारित

यह बिल दो दशक पुराने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा का स्थान लेगा

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली दो दशक पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेने वाले "विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी –जी राम-जी (विकसित भारत जी राम जी) विधेयक 2०25" को लोकसभा ने विपक्षी दलों के कड़े विरोध और भारी हंगामे के बीच गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

लोकसभा में वीबी –जी राम-जी विधेयक पर बुधवार देर रात तक करीब नौ घंटे चर्चा चली और सभी दलों के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि चर्चा में 98 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को चर्चा का जवाब दिया जिसके बाद विधेयक को पारित कर

- विकसित भारत जी राम जी बिल पर लोकसभा में बुधवार देर रात तक लगभग 9 घंटे चर्चा चली तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहस का जवाब दिया।**

दिया गया। चौहान ने कहा कि विधेयक महिला, युवा, गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के साथ ही बापू के सपनों और उनके आदर्शों को ज़िंदा रखने में अहम भूमिका निभाएगा और यह कानून गरीबों की ज़िंदगी बदलकर आदर्श ग्राम स्थापित करेगा जिसमें लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मनरेगा कानून 2०05 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में बना था और उस सरकार का यह उसके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। मनरेगा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को न्यूनतम 1०0 दिन सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी दी गयी। वीबी जी राम

जी विधेयक में 1०० के स्थान पर न्यूनतम 125 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रस्ताव है। खेती-बाड़ी में श्रमिकों की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए बुवाई-कटाई के मौसम में वर्ष में 6० दिन तक इस योजना के काम को स्थगित रखा जा सकता है। यह फैसला राज्य सरकारों के हाथ में होगा कि किस समय इसे स्थगित रखना है।

इसे केंद्र प्रायोजित योजना बनाया गया है और केंद्र तथा राज्य का अंशदान 6०:4० के अनुपात में होगा। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 9० प्रतिशत धन केंद्र देगा। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहां पूरा खर्च केंद्र उठाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार का विकसित भारत जी राम जी बिल गरीब विरोधी है

- कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा रोजगार अवधि 100 से 125 दिन करना एक चालाकी है, इस स्क्ीम से आने वाले दिनों में मनरेगा योजना खत्म हो जाएगी।**

महीनों में मनरेगा खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसका बोझ राज्यों पर पड़ेगा, यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करने वाले इस विधेयक का उनका गठबंधन पूरी तरह से विरोध करेगा। सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर सहमत हैं और एकजुट है।

वाड़ा ने इस विधेयक को मनरेगा खत्म करने की योजना बताते हुए कहा "1०0 दिन से 125 दिन की सजदूरी वाली बात सिर्फ एक चालाकी है। इस

बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे-धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी।

मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालात में भी उनके साथ थी। यह विधेयक गरीब-मजदूरों के खिलाफ है, हम इसका सख्त विरोध करेंगे।

इससे पहले कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन परिसर

में इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएफके के टीआर बाबू, समाजवादी पार्टी के धर्मरंज यादव, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन सहित, कई दलों के सांसद शामिल हुए।

प्रदर्शन के बाद खरगे ने कहा, "यह मनरेगा का केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना की योजनाबद्ध हत्या है। नये विधेयक के जरिए भाजपा सरकार उस अधिकार को छीन रही है, जो कांग्रेस ने दिया था। यह काम के अधिकार को छीनने की कोशिश है।

कोलकाता, 18 दिसंबर। ओडिशा के नंदनकानन से लाई गई 34 महीने की एक बाधिन की दक्षिण कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में अज्ञात बीमारी से मौत हो गई।
रॉयल बंगाल टाइगर की यह तीसरी मौत है, जिससे पश्चिम बंगाल में पशु प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है।
उल्लेखनीय है कि यह बाधिन फरवरी 2०23 में ओडिशा के नंदनकानन में पैदा हुई थी और उसी साल आगस्त में कोलकाता लाई गई थी। बुधवार को अलीपुर चिड़ियाघर में अपने पिंजरे में वह मृत पाई गई। अलीपुर चिड़ियाघर की निदेशक तुषिा ने बताया कि पोस्टमार्टम किया गया है और युवा बाधिन को असमय मौत के कारण का पता लगाने के लिए विवरण जांच किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाधिन होमोप्रोटोडोअन पैरासाइट से होने वाले संक्रमण से पीड़ित थी। उसे चिड़ियाघर के स्वास्थ्य सुविधा

‘बोतलबंद पानी की ...

लिए भूमिगत जल पर निर्भर है। “यह एक शहर-केन्द्रित दृष्टिकोण है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूमिगत जल पीते हैं, और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती।”

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अगर याचिका उन क्षेत्रों पर केंद्रित होती, जहां पीने के पानी की बुनियादी सुविधाएं नहीं नहीं हैं, तो वह मामला अलग तरीके से देख सकते थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “पानी की बोतल में यह सामग्री होनी चाहिए, वह सामग्री होनी चाहिए, ये सब लगभगी मुकद्दमे हैं।”

जब वकील ने इस मामले को लगभगी मुकद्दमा कहने पर असहमत होकर इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर जोर दिया, तो बेंच ने कहा कि वे याचिका मौजूदा वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर रही हैं।

सीजेआई ने कहा, “क्या आप सोचते हैं कि हम, यूएसए, ईयू या जापान के दिशा निर्देश लागू कर सकते हैं? चलिए, देश की वास्तविकताओं को देखते हैं। कोई भी गरीबों का मुद्दा नहीं उठाता, यह अमीरों और शहरीकरण का डर है।”

हालांकि, याचिका में कहा गया है कि तुल्य स्वास्थ्य संगठन के मानकों की वजह में भारतीय मानकों की स्वीकार्य सीमाएं पुरानी हैं, पर कोर्ट ने इस पर जाँच से इन्कार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उचित प्राधिकृत प्राधिकरण से संपर्क

करने का अधिकार दिया।
अंतिम टिप्पणी में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “जब गांधी भारत लौटे थे, तो वे सबसे पहले गरीब क्षेत्रों में गए थे। याचिकाकर्ता से कहिए कि वे उन क्षेत्रों में जाएं, जहां लोग पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करते हैं, तब उनकी समझ में आएगा कि भारत वास्तव में किस समस्या का सामना कर रहा है।”

रीट पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अदालत के छह माह में अभियोजन साक्ष्य पुरा नहीं करने पर उसे नए सिरे से जमानत अजी पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से समयबद्ध निर्देश प्राप्त होने के बाद भी, निचली अदालत ने अभी तक आरोप तय नहीं किए हैं। ऐसे में मूल मामले के साथ ही इस ईंडी केस में भी सुनवाई आरंभ नहीं हुई है। मूल मामले में याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा है और ईंडी केस में एक साल से जेल में बंद है।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में 3० गवाहों के साथ ही हजारों दस्तावेज पेश हुए हैं, जिनका परीक्षण ईंडी कोर्ट को करना है। गवाहों में अधिकतम सरकारी कर्मचारी हैं और उनके प्राविधित होने की आशंका नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

माईन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा,
एच.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386०32,फैक्स:०744-2386०33, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413०92, फैक्स : ०294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:०145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्टीयल एरिया, फैस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: ०2973-226424
हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-2०1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 23०200, 23०400, फैक्स: ०7469-23०600
चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 2569०6, 2569०7, फैक्स: ०1562-2569०8

